

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 17/2015

दिलीप सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, हनुमानगढ़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2015

आदेश की दिनांक : 09.05.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 01.07.1986 के द्वारा अध्यापक ग्रेड-तृतीय के पद पर दी गई थी। उसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 02.07.1986 को कार्य ग्रहण किया। अपीलार्थी के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06.04.1988 एवं 11.08.1989 के आधार पर स्क्रीनिंग की एवं अपीलार्थी की सेवाएं नियमित की गयी। अपीलार्थी की 9 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 1995 में दिया गया, जो कि प्रथम नियुक्ति की दिनांक 02.07.1986 से गणना करने के उपरान्त दिया गया। अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था परन्तु अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ स्क्रीनिंग की दिनांक 18.01.1990 से सेवा की गणना करके दिया गया, जबकि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 02.07.1986 से सेवा की गणना करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी दिनांक 02.07.2013 को हो गया था, परन्तु अपीलार्थी को वह लाभ भी प्रदान नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:-

"It is, therefore, most respectfully prayed that this appeal may kindly be accepted and allowed and call for the entire record relating to the case of the appellant and after examining the same, the impugned orders dated 23-3-2011, may kindly be quashed and set aside and the respondents be directed to revise the benefit of second selection grade/ACP and further be granted the benefit of third selection grade/ACP by counting his services from the date of initial appointment i.e. 2-7-1986 and in consequences arrears be also granted to the appellant with interest of 9% per annum.

Any other appropriate order or direction which this Hon'ble Court deems fit and proper may kindly be passed in favour of the appellant."

2. इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. दोनों पक्षों को मौखिक रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिनांक 02.07.1986 से लगातार सेवा में है और अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना करते हुए प्रदान किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी आगामी चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 02.07.1986 से गणना करते हुए प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवाएं जिला स्थापना समिति द्वारा स्क्रीनिंग के पश्चात नियमित की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी स्क्रीनिंग की दिनांक से नियमित सेवा में माना जा सकता है और अपीलार्थी को नियमितकरण की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी रूप से हुई थी। बाद में अपीलार्थी की सेवाएं स्क्रीनिंग के पश्चात नियमित की गई है।
4. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:—

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

5. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में यह माना गया है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। यह

भी माना है कि वरिष्ठता या अन्य लाभ के संबंध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारीख नहीं हो सकती। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी को अस्थाई तौर पर तदर्थ आधार पर जो सेवाएं प्रदान की थी, उसे अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लाभ के लिए नहीं जुड़वा सकता है। अपीलार्थी को नियमितिकरण की दिनांक से ही नियमित होना मानते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है।

6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)